भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 854
जिसका उत्तर शुक्रवार, 07 फरवरी, 2025 को दिया जाना है

महिला अधिवक्ताओं के लिए सुविधाएं

854. डॉ. गणपथी राजकुमार पी.:

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय और देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में महिला अधिवक्ताओं को प्रदान की जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) देश में महिला अधिवक्ताओं को पर्याप्त वित्तीय सहायता के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या बार एसोसिएशन की नौकरी और उच्च शिक्षा में नामांकन के लिए महिला अधिवक्ताओं के लिए कोई आरक्षण है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : भारत का उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने महिला अधिवक्ताओं की सहायता के लिए विशेष सुविधाएं लागू की हैं । उच्चतम न्यायालय, अनन्य रूप से महिला अधिवक्ताओं के लिए समर्पित शौचालय, प्रतीक्षा क्षेत्र और लाउंज उपलब्ध कराता है । छोटे बच्चों वाली महिला अधिवक्ताओं की सहायता के लिए, न्यायालय परिसर के भीतर एक बाल देखभाल केंद्र (क्रेच) की स्थापना एक उल्लेखनीय सुविधा है, साथ ही न्यायालय परिसर के भीतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निगरानी प्रणाली जैसे उन्नत सुरक्षा उपाय भी किए गए हैं ।

इसी प्रकार, देशभर के विभिन्न उच्च न्यायालयों ने महिला अधिवक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधाएं आरंभ की है । कुछ उच्च न्यायालयों में महिला अधिवक्ताओं के लिए अनन्य रूप से शौचालय, लाउंज और चेंजिग कक्ष के साथ-साथ, लिंग विशिष्ट चिंताओं पर केंद्रित अलग महिला बार एसोसिएशन या समितियां हैं । इसके अतिरिक्त, कई उच्च न्यायालयों ने बेहतर प्रकाश व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी, और सुरक्षा कर्मियों की उपस्थिति, विशेषकर ऐसे क्षेत्रों में, जिनमें महिला अधिवक्ताओं का विशेष रूप से जाना होता हैं, के माध्यम से सुरक्षा में सुधार किया है । न्यायालय, ने विधिक वृत्ति में महिलाओं के लिए विधिक अधिकार और कार्यस्थल सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए लिंग-संवेदनशीलता कार्यक्रम और कार्यशालाएं भी आयोजित करते हैं ।

(ख) : विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के प्रशासन से संबंधित है, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन, महिलाओं के लिए कोई विशेष उपबंध नहीं है । सभी वर्गों के अधिवक्ताओं को एक समान दर्जा दिया गया है । चूंकि, केंद्रीय विधान, लिंग-विशिष्ट उपबंध नहीं कर सकता है, विभिन्न राज्य बार काउंसिल/बार एसोसिएशन ने वित्तीय रूप के साथ, विभिन्न तरीकों से महिला अधिवक्ताओं का समर्थन करने के लिए स्कीमें शुरू की है ।

(ग) से (ङ) : अधिवक्ता अधिनियम, 1961, महिलाओं के आरक्षण के लिए कोई विशेष उपबंध नही करता है । अधिनियम, सभी वर्गों के अधिवक्ताओं के साथ एक समान व्यवहार करता है । बीसीआई द्वारा सूचित किए अनुसार, इसने राज्य बार काउंसिलों को परिषद् की विभिन्न अनुशासनात्मक और अन्य समितियों में कम में कम 25% महिलाओं को सहयोजित करने का सक्रिय रूप से निर्देश दिया है । इस निर्देश का उद्देश्य विधिक बिरादरी के अंदर निर्णय लेने वाले निकायों मे महिलाओं का अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है, जिससे समानता और विविधता का वातावरण विकसित हो सके ।

****